विशेषज्ञों को एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार

मंत्री पीयूष गोयल ने प्रौद्योगिकी उन्नयन पर दिया बल

एशियाई उत्पादकता संगठन की बैठक राजधानी में शुरू

नई दिल्ली, 22 मई. राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ) की संचालन परिषद के 68वें सत्र के पहले दिन गुरुवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब उत्पादकता केवल दक्षता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लचीलापन, नवाचार और समावेशी विकास के पहलू भी जुड़े हैं.

भारत मंडपम में चल रही इस बैठक में सदस्य देशों के राष्ट्रीय उत्पादकता संगठनों (एनपीओ) के प्रमुख, नीति निर्माता, उत्पादकता विशेषज्ञ तथा एपीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.बैठक के उद्घाटन सत्र में श्री गोयल मुख्य अतिथि थे. सत्र के उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि एपीओ की संचालन परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत को एपीओ के परिवर्तनकारी दौर में योगदान देने का अवसर मिला, जहाँ प्रौद्योगिकी, सतत विकास और बदलती वैश्विक परिस्थितियाँ अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार दे रही हैं.

उन्होंने भारत में मोदी सरकार के सुधारों का उल्लेख करते हुए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाएँ, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, यूपीआई, आधार और डिजिटल वाणिज्य के खुले नेटवर्क (ओएनडीसी) जैसी पहलों को उत्पादकता-आधारित परिवर्तन के उदाहरण बताया.

साथ ही उन्होंने एपीओ के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग, सतत विकास और भविष्य के लिए तैयार विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई.

> उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने उद्घाटन सत्र में कहा कि एपीओ विजन 2030 और रणनीतिक सुधार सदस्य देशों में संस्थागत सहयोग, सुशासन और परिणाम-आधारित विकास को और मजबूत करेंगे .इस सत्र में श्री गोयल ने उत्पादकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले कुछ विशेषज्ञों को एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए .

एसबीआई में 6 दिन ताले ग्राहकों की बढ़ेगी परेशानी

नई दिल्ली 22 मई. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 23 मई से 28 मई तक लगातार छह दिनों तक कामकाज प्रभावित रहेगा.

वीकेंड की छुट्टियां, कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल और बकरीद के त्योहार को लेकर घोषित अवकाश के कारण बैंक शाखाओं में सामान्य सेवाएं ठप रहने की संभावना है. इसका असर करोड़ों ग्राहकों पर पड़ सकता है, खासकर उन लोगों पर जो नकद लेनदेन और शाखा आधारित सेवाओं पर निर्भर हैं.

23 मई को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे, जबकि 24 मई को रविवार की नियमित छुट्टी रहेगी. इसके बाद 25 और 26 मई को ऑल इंडिया स्टेट बैंक स्टाफ फेडरेशन ने दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है.

अमेरिकी हाईटेक कंपनियों के साथ करें जॉइंट वेंचर

लॉजिस्टिक्स लागत 16 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत रह गई : नितिन गडकरी

नई दिल्ली, 22 मई. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय कंपनियों को नवीनतम तकनीकों तक पहुंच हासिल करने के लिए अमेरिकी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम करने की जरूरत है.

बीते गुरुवार को अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि अमेरिकी कंपनियां नई तकनीकों का विकास कर रही हैं.ऐसे में भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करना बेहद जरूरी है.

उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय हाईवे परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में अमेरिकी कंपनियों से परामर्श लेने पर भी विचार कर रहा है. गडकरी ने कहा कि लॉजिस्टिक्स में सप्लाई चेन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक्सप्रेसवे तथा आर्थिक कॉरिडोर के तेजी से विस्तार के कारण भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अब एकल अंक तक पहुंच गई है.

उन्होंने बताया कि आईआईटी चेन्नई, आईआईटी कानपुर और आईआईएम बेंगलुरु द्वारा तैयार ताजा अध्ययन के अनुसार, एक्सप्रेसवे और आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण से भारत की लॉजिस्टिक्स लागत 16 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत रह गई है.

> गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर-1 बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है .उन्होंने कहा कि जब मैंने परिवहन मंत्री का कार्यभार संभाला था, तब भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार 14 लाख करोड़ रुपये था .अब यह बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है . केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर लगभग 4 लाख युवाओं को रोजगार देता है और केंद्र तथा राज्यों को सबसे अधिक जीएसटी भी इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है .

निजी क्षेत्र के बैंकों, गैर बैंकिग शेयरों को निवेशकों का समर्थन

मुंबई, 22 मई. निजी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय सेवा कंपनियों के शेयरों को निवेशकों के समर्थन तथा इंजीनियरिंग और अवसंरचना क्षेत्र से जुड़ी कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयरों में लिवाली निकलने से स्थानीय शेयर बाजारों के प्रमुख शेयर सूचकांक शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए.

शुरुआती कारोबार में रुपये की विनिमय दर में सुधार के संकेतों से भी बाजार को समर्थन मिला. बंबई बाजार का सेंसेक्स 231.99 अंक या 0.31 प्रतिशत बढ़कर 75,415.35 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 64.60 अंक या 0.27 प्रतिशत बढ़कर 23,719.30 पर बंद हुआ .सेंसेक्स सुबह 75,260.39 पर खुलने के बाद ऊपर में 75,810.97 और नीचे में 75,230.75 अंक तक गया था.कल बाजार 75,183.36 पर बंद हुआ था.इसी तरह निफ्टी50 सुबह 23,671.20 पर खुल कर ऊपर में 23,835.65 और नीचे में 23,671 तक गया था. बीएसई में आज साप्ताहिक कारोबार के आखिरी दिन 15 शेयर लाभ में और 15 हानि में रहे.लाभ में रहे प्रमुख शेयरों में ट्रेन्ट 3.01 प्रतिशत, एक्सिस 2.52 प्रतिशत, आईसीआईसीआई बैंक 1.77 प्रतिशत, एशियन पेंट 1.56 प्रतिशत और हिंदुस्तान लीवर 1.06 प्रतिशत लाभ में रहा.

वैश्विक शांति और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण क्षण

आचार्य बालकृष्ण आई एम पीसकीपर-चैंपियन हेल्थ अवार्ड 2026 से सम्मानित

हरिद्वार, 22 मई. योग, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान परंपरा के पथ-प्रदर्शक आचार्य बालकृष्ण को अंतरराष्ट्रीय मंच पर आज एक और प्रतिष्ठित सम्मान से अलंकृत किया गया.मुंबई में आयोजित वैश्विक बिल्ड्रिओनाइरेस फॉर पीस कॉन्क्लेव 2026 में उन्हें आई एम पीसकीपर- चैंपियन हेल्थ अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया.

यह सम्मान विश्व शांति, मानवता, स्वास्थ्य सेवा और वैश्विक कल्याण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया. आचार्य बालकृष्ण को यह सम्मान ऐसे समय में प्राप्त हुआ है जब आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति को पूरी दुनिया में अभूतपूर्व स्वीकार्यता मिल रही है.उन्होंने अपने अनुकरणीय शोध, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैश्विक प्रयासों के माध्यम से आयुर्वेद को केवल पारंपरिक चिकित्सा पद्धति तक सीमित नहीं रहने दिया, अपितु उसे आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और समग्र स्वास्थ्य के साथ जोड़कर नई दिशा प्रदान की है.उनके नेतृत्व में पतंजलि द्वारा भारतीय पौराणिक ग्रन्थों में समाहित ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साक्ष्य-आधारित परिणामों में माध्यम से विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है.

सम्मान प्राप्त करने के उपरांत आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि एक स्वस्थ मानव ही शांतिपूर्ण समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है.

> आयुर्वेद मात्र एक चिकित्सा पद्धति नहीं, अपितु सम्पूर्ण मानवता को संतुलित, निरोग और सकारात्मक जीवन की दिशा प्रदान करने वाला विज्ञान है . भारत सदैव वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना का प्रतिनिधित्व करता आया है और आज पूरी दुनिया शांति, सहअस्तित्व और समग्र स्वास्थ्य के लिए भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रही है .आज विश्व जिस मानसिक तनाव, असंतुलित जीवनशैली और स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा है, उसका समाधान प्रकृति और भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित है .योग और आयुर्वेद विश्व को केवल रोगमुक्त ही नहीं, बल्कि तनावमुक्त और संघर्षमुक्त जीवन की दिशा भी प्रदान करते हैं .

सेंट्रल बैंक में हिस्सेदारी बेचकर 2455 करोड़ जुटाएगी सरकार

मुंबई, 22 मई. केंद्र सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है. सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए बैंक में 8 प्रतिशत तक स्टेक बेचकर करीब 2,455 करोड़ जुटाने की तैयारी में है. इसके लिए फ्लोर प्राइस 31 प्रति शेयर तय किया गया है, जो बैंक के गुरुवार के बंद भाव 33.94 से लगभग 8.5 प्रतिशत कम है.

इस घोषणा के बाद शुक्रवार को बैंक के शेयरों में 5 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई और शेयर करीब 32 के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया. डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, ओएफएस प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी. नॉन-रिटेल निवेशकों के लिए यह ऑफर 22 मई को खुलेगा, जबकि रिटेल निवेशक और बैंक कर्मचारी 25 मई को बोली लगा सकेंगे. दोनों दिन सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे. सरकार बेस ऑफर के तहत 4 प्रतिशत हिस्सेदारी यानी 36.20 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी. अगर निवेशकों की मांग अच्छी रही तो अतिरिक्त 4 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा.

9.6 प्रतिशत बढ़ी रेपको की ऋण पुस्तिका

वित्त वर्ष 2025-26 में मजबूत प्रदर्शन, घटा एनपीए

चेन्नई 22 मई . रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज हुई बैठक में 31 मार्च 2026 को समाप्त चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2025-26 के भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार वित्तीय परिणामों को मंजूरी दे दी.

कंपनी ने इस दौरान ऋण वितरण, आय और मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की, जबकि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी देखने को मिली.

31 मार्च 2026 तक कंपनी की कुल ऋण पुस्तिका 15,880 करोड़ रुपये रही, जो एक वर्ष पहले 14,492 करोड़ रुपये थी. इस प्रकार कंपनी ने 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की. 31 दिसंबर 2025 तक प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां 15,394 करोड़ रुपये रहीं.

कंपनी की कुल ऋण पुस्तिका में गैर-वेतनभोगी वर्ग के ऋणों की हिस्सेदारी 53 प्रतिशत रही, जबकि वेतनभोगी वर्ग का हिस्सा 47 प्रतिशत रहा. आवास ऋण कुल ऋणों का 71 प्रतिशत रहे, जबकि गृह इक्विटी उत्पादों की हिस्सेदारी 29 प्रतिशत रही. कंपनी द्वारा दिए गए सभी ऋण खुदरा श्रेणी के हैं.

परिसंपत्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर भी सुधार दर्ज किया गया. सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां घटकर 405 करोड़ रुपये रह गईं, जो 31 मार्च 2025 को 473 करोड़ रुपये थीं. वहीं शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां 183 करोड़ रुपये रहीं, जो एक वर्ष पहले 191 करोड़ रुपये थीं.

> वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण स्वीकृतियां 4,519 करोड़ रुपये रहीं, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक हैं . इसी अवधि में ऋण वितरण 4,148 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई . कंपनी की कुल आय बढ़कर 1,798 करोड़ रुपये हो गई, जबकि शुद्ध ब्याज आय 812 करोड़ रुपये रही . वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का शुद्ध लाभ 453 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में 449 करोड़ रुपये था . ऋण स्प्रेड 3 .3 प्रतिशत पर मजबूत बना रहा .

अवध एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर को मजबूत करेगा

नई दिल्ली.अचल सम्पत्ति बाजार की प्रतिष्ठित परामर्श सेवा कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया का अनुमान है कि जल्द ही शुरू होने वाला लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा. कुल 63 किलो मीटर की यह नयी राष्ट्रीय राजगार्म परियोजना लखनऊ और कानपुर को जोड़ती है और उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन इकाइयों के लिए विकसित किये जा रहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के दो मुख्य केंद्रों के बीच सम्पर्क सुविधा मज़बूत करती है

मर्सिडिज-बेंज ने पेश किए नाइट एडिशन

पुणे, 22 मई. लग्जरी कार निर्माता मर्सिडिज-बेंज ने गुरुवार को जीएलई और जीएलएस के नाइट एडिशन बाजार में उतारने की घोषणा की. ये दोनों विशेष और लिमिटेड-सीरीज मॉडल हैं, जिनमें कंपनी की सबसे अधिक बिकने वाली लग्ज़री एसयूवी रेंज जीएलई और जीएलएस को एक अलग लुक और विशेष इंटीरियर के साथ पेश किया गया है.

नाइट एडिशन जीएलएस 450 की एक्स-शोरूम कीमत 1.41 करोड़ रुपये और नाइट एडिशन जीएलएस 450डी की कीमत 1.43 करोड़ रुपये रखी गयी है.नाइट एडिशन जीएलई 300डी की एक्स-शोरूम कीमत 1.05 करोड़ रुपये और जीएलई 450 की कीमत 1.14 करोड़ रुपये है.कंपनी ने बताया कि ये नाइट एडिशन ऐसे विशेष कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होंगे, जो किसी भी मानक संस्करण से अलग हैं.यह एक वैश्विक लिमिटेड सीरीज़ का हिस्सा है और विभिन्न बाजारों में सीमित संख्या में पेश किया जायेगा, जिससे इसकी विशिष्टता और कलेक्टर अपील और बढ़ जाती है.

समाचार विशेष

भाजपा खेलेगी अंतरात्मा वाला सुपर दांव

राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने गड़ाई तीनों सीटों पर नजरें

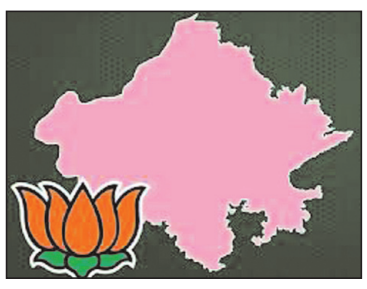

जयपुर. राजस्थान में सियासत की नई बिसात बिछने लग गई है. इसकी वजह है राज्यसभा चुनाव. आगामी 21 जून को राजस्थान के तीन राज्यसभा सांसद रिटायर हो जाएंगे. लिहाजा तीन सीटें खाली हो जाएंगी. इन तीनों सीटों पर काबिज होने के लिए सत्तारुढ बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है.

पार्टी के विधानसभा सदस्यों की संख्या को देखते हुए बीजेपी के खाते में दो सीटें फिर से आना तय है लेकिन उसकी कोशिश तीनों सीटों पर काबिज होने की है. तीसरी सीट को भाजपा 'अंतरात्मा की आवाज' के जरिए जीतने का ख्वाब देख रही है. इसके लिए बीजेपी तीनों सीटों के लिए नामों का पैनल तैयार कर रही है.

राजस्थान से खाली हो रही राज्यसभा की तीन सीटों पर फिलहाल भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी काबिज हैं. इनका कार्यकाल 21 जून को पूरा होने जा रहा है. राज्यसभा में राजस्थान की कुल 10 सीटें हैं. राजस्थान विधानसभा के कुल सदस्यों में भाजपा और कांग्रेस के पास जो संख्या है उससे पुरानी स्थिति ही वापस बनेगी. यानी समीकरणों के अनुसार भाजपा के पास दो और कांग्रेस के पास एक सीट जीतने लायक संख्या मौजूद है.

प्रत्येक सीट के लिए प्रथम वरीयता के 51 वोट चाहिए- राज्यसभा की तीन सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए प्रत्येक सीट के लिए प्रथम वरीयता के 51 वोट चाहिए. भाजपा के पास दो सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में वोट हैं. उसे दो सीटों के लिए प्रथम वरीयता वाले 102 वोट चाहिए. 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में बीजेपी के पास 118 और कांग्रेस के पास वर्तमान में 67 सीटें हैं. लिहाजा कांग्रेस के पास भी एक सीट के लिए पर्याप्त वोट संख्या है. उसे एक सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 51 वोट चाहिए. लेकिन फिर भी भाजपा तीसरी सीट की उम्मीद लगाए बैठी है.

> **'अंतरात्मा की आवाज' के नाम पर मिल सकता है वोट**
>
> भाजपा का राजस्थान नेतृत्व मान रहा है कि यदि विपक्षी खेमे में नाराजगी बढ़ी तो कुछ विधायक 'अंतरात्मा की आवाज' के नाम पर वोट डाल सकते हैं . राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान भी इसी रणनीति की ओर संकेत करता है . उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारा विरोधी कल हमारा प्रशंसक बने . आज हमारा प्रशंसक कल हमारा मतदाता बने . आज हमारा मतदाता कल हमारा कार्यकर्ता बने और आज जो हमारा कार्यकर्ता है वह कल नेता बने . हम इस नीति पर काम कर रहे हैं . राजनीतिक गलियारों में इसे चुनावी सेंधमारी के रूप में देखा जा रहा है .

आदि कैलास से भाजपा का शंखनाद

हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र बना उत्तराखंड

देहरादून. दो दिनों तक चीन सीमा से लगे गुंजी और आदि कैलास की कंदराओं में गूंजते रहे हर हर महादेव, भारत माता की जय और जय श्रीराम के नारों के बीच भाजपा का प्रशिक्षण शिविर शनिवार को संपन्न हो गया. आदि कैलास की चोटियों पर फिर वही हिम-धवल निस्तब्धता उतर आई है.

ठंडी हवाएं अब भी बह रही हैं, दो दिनों तक इन हवाओं में घुली रही राजनीतिक गर्मी अब स्मृतियों में बदल रही है. भगवा झंडे समेट लिए गए हैं. कार्यकर्ता घरों को लौट गए हैं. हिमालय की गोद में लगा यह शिविर तो समाप्त हो गया, लेकिन सीमांत क्षेत्रों में आगामी वर्षों की भगवा राजनीति का एक खाका दे गया.

ये है पार्टी की नई रणनीति- आदि कैलास व हिमालय की ऊंचाइयों से भाजपा जिस संदेश को पूरे देश तक पहुंचाना चाहती थी, वह साफ तौर पर दिया जा चुका है. भाजपा ने शिविर के जरिए संदेश दिया कि उसकी राजनीति अब केवल चुनाव प्रबंधन तक सीमित नहीं, बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सीमांत क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना व आध्यात्मिक प्रतीकों से वैचारिक विस्तार पार्टी की नई रणनीति है. दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन या संगठनात्मक कौशल तो सिखाया ही गया, इसके साथ ही एकात्म मानव दर्शन, पंचनिष्ठा, सनातन परंपरा के जरिये भविष्य की राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भूमिका से भी अवगत कराया गया. हिमालय को राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में स्थापित कर भाजपा ने गुंजी शिविर के जरिए सीमांत क्षेत्रों से वैचारिक और राजनीतिक रिश्ता मजबूत करने की कोशिश की.

वेणुगोपाल की अब क्या हैसियत है

नई दिल्ली. कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को लेकर अब दो तरह की चर्चा है. उनके करीबियों का कहना है कि उन्होंने केरल में मुख्यमंत्री पद का त्याग किया, जिसकी वजह से उनका कद बढ़ गया है.

कुछ पत्रकार भी इस लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं. दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का एक खेमा है, जो कह रहा है कि वेणुगोपाल ने पूरी मेहनत की और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए इससे उनकी हैसियत बहुत कम है. यह धारणा बनी है कि जब वे खुद अपने लिए कुछ नहीं ले सकते हैं तो दूसरे किसी नेता क्या दिलवा सकते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दूसरी धारणा ज्यादा तार्किक और सही है. कांग्रेस नेता वेणुगोपाल की हैसियत का अंदाजा इसी आधार पर कर रहे हैं कि उन्होंने केरल का मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी. लेकिन राहुल गांधी ने उनको नहीं बनाया.

राहुल और प्रियंका गांधी ने अंतिम फैसला वीडी सतीशन के पक्ष में किया. कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता उनको चाहते थे और पार्टी की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी उनके नाम पर वीटो किया था.

विशेष | बदले हुए नियमों से तय होगी प्रधानी की किस्मत

पंचायत चुनाव पर योगी सरकार का बड़ा दांव

लखनऊ. योगी सरकार ने पंचायत चुनावों की तारीखों पर लगी अनिश्चितता को दूर करने की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम उठा लिया है. अब प्रधानी से लेकर जिला पंचायत तक का सफर पुराने ढर्रे पर नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बेहद कड़े 'ट्रिपल टेस्ट' के जरिए तय होगा. यह केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि ग्रामीण सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह बदलने वाला ऐतिहासिक मोड़ है, जिसका सीधा असर आपके गांव की राजनीति और आरक्षित सीटों पर पड़ने वाला है.

सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 'समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन को मंजूरी दे दी गई है. इससे पहले साल 2021 के चुनावों में केवल रैपिड सर्वे के आधार पर सीटें तय कर दी गई थीं, जिसे लेकर काफी कानूनी विवाद हुए थे. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि बिना वैज्ञानिक और अनुभवजन्य आंकड़ों के राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता. अब सरकार ने इस विधिक अड़चन को दूर कर दिया है. इसका मतलब यह है कि अब आरक्षण की सूची हवा-हवाई नहीं होगी, बल्कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हर जिले की सटीक स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी.

क्या हैं तीन कसौटियां जिसे पार करना जरूरी?- सुप्रीम कोर्ट का यह 'ट्रिपल टेस्ट' फॉर्मूला तीन मुख्य शर्तों पर टिका है. पहली शर्त है एक समर्पित आयोग का गठन, जो यूपी के गांवों में जाकर ओबीसी वर्ग के पिछड़ेपन की गहन जांच करेगा. दूसरी शर्त यह है कि आयोग द्वारा जुटाए गए जमीनी आंकड़ों के आधार पर ही सीटों का सटीक प्रतिशत तय होगा. और सबसे महत्वपूर्ण तीसरी शर्त यह है कि किसी भी हाल में एससी, एसटी और ओबीसी का कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा को पार नहीं करना चाहिए. यदि सरकार इन शर्तों को पूरा किए बिना चुनाव कराती है, तो उन सभी ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी में मान लिया जाएगा, जो राजनीतिक रूप से एक बड़ा जोखिम हो सकता है.

> **आखिर कब बज सकता है गांवों में चुनावी बिगुल**
>
> इन सभी तकनीकी और कानूनी प्रक्रियाओं को देखते हुए यह साफ है कि चुनावी मैदान सजने में अभी कुछ महीनों का वक्त और लगेगा . आयोग का कार्यकाल छह महीने तय किया गया है . रिपोर्ट आने के बाद नई आरक्षण सूची यानी रोटेशन पॉलिसी पर आपत्तियां मांगी जाएंगी और उनका निस्तारण होगा . इन तमाम समीकरणों को देखकर जानकार मान रहे हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद ही, यानी फरवरी या मार्च के आसपास ही पंचायत चुनावों की आहट सुनाई देगी . तब तक गांवों में प्रधानी की कुर्सी का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है, लेकिन यह साफ है कि इस बार चुनाव पूरी तरह विधिक पारदर्शिता के साथ होंगे .